

डिजिटलीकरण और ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन फतेहपुर जनपद में शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक संबंधों पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

नीलम देवी¹ & डॉ० मुहम्मद रफ़ीक²

¹शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, हलीम मुस्लिम महाविद्यालय कानपुर उ.प्र.।

²असिस्टेंट प्रोफेसर, हलीम मुस्लिम महाविद्यालय कानपुर उ.प्र.।

Received: 20 June 2026 Accepted & Reviewed: 25 Sep 2026, Published: 30 September 2026

Abstract

वर्तमान समय में डिजिटलीकरण भारतीय समाज में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में उभरा है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ईगवर्नेंस, सोशल मीडिया तथा विभिन्न डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने ग्रामीण जीवन को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का प्रभाव केवल संचार के साधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों, सरकारी सेवाओं तक पहुँच, सामाजिक संबंधों, पारिवारिक संरचना तथा ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं में भी परिवर्तन दिखाई देता है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के संदर्भ में डिजिटलीकरण के कारण ग्रामीण- समाज में उत्पन्न सामाजिक परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंधों पर केंद्रित है। इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता, लैंगिक डिजिटल विभाजन, आर्थिक असमानता, डिजिटल सेवाओं तक पहुँच तथा साइबर जोखिम जैसी चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह प्रतिपादित होता है कि डिजिटलीकरण ग्रामीण समाज के लिए सामाजिक एवं आर्थिक अवसरों का विस्तार करने की क्षमता रखता है, किंतु इसके लाभों का समान वितरण डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षा, आय, लैंगिक स्थिति और डिजिटल कौशल पर निर्भर करता है। अतः ग्रामीण डिजिटलीकरण को केवल तकनीकी विकास के रूप में न देखकर सामाजिक समावेशन और ग्रामीण सशक्तिकरण की प्रक्रिया के रूप में समझना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: डिजिटलीकरण, ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक संबंध, डिजिटल विभाजन, फतेहपुर।

Introduction

इक्कीसवीं शताब्दी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने सामाजिक परिवर्तन की गति को अत्यधिक तीव्र किया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के विस्तार ने सूचना के उत्पादन, वितरण और उपभोग की पारंपरिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। इसका प्रभाव शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जिन कार्यों के लिए- पूर्व में लोगों को सरकारी कार्यालयों, बैंकों, विद्यालयों अथवा बाजारों तक जाना पड़ता था, उनमें से अनेक कार्य अब डिजिटल माध्यम से संभव हो रहे हैं। भारत में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार ने ग्रामीण क्षेत्रों को इस परिवर्तन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मई 2025 तक देश के लगभग 97.65 प्रतिशत गाँव मोबाइल कनेक्टिविटी तथा 96.80 प्रतिशत गाँव 4G मोबाइल कनेक्टिविटी के दायरे में बताए गए थे। भारतनेट परियोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। इसी प्रकार Common Service Centres ग्रामीण स्तर पर सरकारी, वित्तीय, सामाजिक तथा निजी सेवाओं की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल माध्यम बनकर सामने आए हैं। ग्रामीण समाज पर डिजिटलीकरण के प्रभाव को केवल तकनीकी सुविधा के आधार पर नहीं समझा जा सकता। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है कि डिजिटल तकनीक ग्रामीण व्यक्तियों के व्यवहार, पारिवारिक संबंधों, सामाजिक संपर्क, शिक्षा, आजीविका, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सामाजिक असमानताओं को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने एक ओर ग्रामीण युवाओं को वैश्विक सूचनाओं तथा नए रोजगार विकल्पों से जोड़ा है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच ने एक नए प्रकार के सामाजिक विभाजन को भी जन्म दिया है। फतेहपुर जनपद मुख्यतः व्यापक ग्रामीण संरचना वाला क्षेत्र है। जनपद में 13 विकास खंड, 840 ग्राम पंचायतें तथा 1,521 गाँव दर्ज हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल जनसंख्या 26,32,733 थी। ऐसी सामाजिक संरचना में यह जानना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल तकनीक ग्रामीण जीवन की पारंपरिक संरचनाओं को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। प्रस्तुत अध्ययन इसी प्रश्न को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संबंधों के विशेष संदर्भ में समझने का प्रयास करता है।

2. अध्ययन की समस्या

ग्रामीण भारत में डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ा है, किंतु डिजिटल साधनों की उपलब्धता मात्र से सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं होता। किसी परिवार के पास स्मार्टफोन होने और परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग करने का अवसर मिलने में अंतर हो सकता है। इसी प्रकार इंटरनेट उपलब्ध होने और व्यक्ति में डिजिटल सेवाओं का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता होने में भी अंतर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आय, शिक्षा, लिंग, आयु तथा सामाजिक स्थिति डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। शोध साहित्य में भी ग्रामीण महिलाओं की इंटरनेट पहुँच में असमानता तथा सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच डिजिटल विभाजन की समस्या सामने आई है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचा है या नहीं, बल्कि यह है कि इसके सामाजिक लाभ किन समूहों तक, किस सीमा तक और किस स्वरूप में पहुँच रहे हैं। फतेहपुर जनपद के संदर्भ में शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक संबंधों पर डिजिटल परिवर्तन के संयुक्त समाजशास्त्रीय प्रभाव को समझना इसी कारण महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन डिजिटल अवसरों के साथ साथ उनसे उत्पन्न सामाजिक-असमानताओं और चुनौतियों की पहचान करने का प्रयास करता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

- फतेहपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की प्रकृति एवं विस्तार का अध्ययन करना।
- ग्रामीण विद्यार्थियों और युवाओं की शिक्षा पर डिजिटल तकनीक के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों पर डिजिटलीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
- परिवार, समुदाय और पारस्परिक सामाजिक संबंधों में डिजिटल माध्यमों के कारण आए परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
- महिला एवं पुरुषों के मध्य डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग में अंतर का अध्ययन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन तथा डिजिटल साक्षरता से संबंधित प्रमुख समस्याओं की पहचान करना।
- ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में डिजिटल तकनीक की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

4. शोध प्रश्न

प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से इस प्रश्न की पड़ताल करता है कि फतेहपुर जनपद के ग्रामीण समाज में डिजिटलीकरण ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसके अंतर्गत यह जानना आवश्यक है कि डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के अवसरों को किस सीमा तक विस्तृत किया है, ग्रामीण युवाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार संबंधी अवसरों में क्या परिवर्तन आया है तथा परिवार और समुदाय के पारंपरिक सामाजिक संबंध किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। साथ ही यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि क्या डिजिटलीकरण के लाभ समाज के विभिन्न आर्थिक, लैंगिक और शैक्षिक समूहों को समान रूप से प्राप्त हो रहे हैं अथवा इससे नए प्रकार का डिजिटल विभाजन उत्पन्न हो रहा है।

5. परिकल्पनाएँ

अध्ययन में यह परिकल्पना की जा सकती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक के बढ़ते प्रयोग का शिक्षा, रोजगार तथा सूचना तक पहुँच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी परिकल्पना यह है कि डिजिटल साक्षरता का स्तर जितना अधिक होगा, व्यक्ति द्वारा डिजिटल सेवाओं के उपयोग की संभावना उतनी अधिक होगी। तीसरी परिकल्पना के अनुसार आय, शिक्षा तथा लैंगिक स्थिति डिजिटल संसाधनों तक पहुँच को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त यह माना गया है कि सोशल मीडिया एवं डिजिटल संचार के विस्तार से ग्रामीण सामाजिक संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन आया है।

6. शोधपद्धति-

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रखी जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन के लिए अनुसूची, प्रश्नावली तथा आवश्यकतानुसार साक्षात्कार विधि का प्रयोग उपयुक्त होगा। उत्तरदाताओं के चयन में विभिन्न आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और आर्थिक स्तर के ग्रामीण निवासियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

द्वितीयक आँकड़ों के लिए भारत की जनगणना, फतेहपुर जिला प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, Digital India, संबंधित सरकारी रिपोर्टें तथा प्रकाशित शोध पत्रों का प्रयोग किया जा सकता है।-

संकलित प्राथमिक आँकड़ों का प्रतिशत, आवृत्ति तथा आवश्यकतानुसार क्रॉस टैबुलेशन के माध्यम से विश्लेषण किया जा सकता है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के डिजिटल उपयोग में अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा।

7. ग्रामीण समाज और डिजिटलीकरण

भारतीय ग्रामीण समाज लंबे समय तक कृषि, स्थानीय बाजार, पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं तथा प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क पर आधारित रहा है। डिजिटल तकनीक ने इस व्यवस्था में नई प्रकार की गतिशीलता उत्पन्न की है। मोबाइल फोन अब केवल बातचीत का माध्यम नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन, सरकारी सेवाओं, बाजार संबंधी सूचना और सामाजिक संपर्क का बहुउद्देशीय साधन बन गया है।

ग्रामीण नागरिक डिजिटल माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बैंक खाते से संबंधित गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं और ऑनलाइन दस्तावेजों एवं सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। CSC को गाँव स्तर पर सरकारी, वित्तीय, सामाजिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं के वितरण के लिए ICT-सक्षम केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस परिवर्तन ने ग्रामीण नागरिक और प्रशासन के मध्य संपर्क के स्वरूप को भी प्रभावित किया है।

डिजिटलीकरण ने ग्रामीण व्यक्ति की सूचना निर्भरता को स्थानीय सीमाओं-से बाहर निकाला है। अब किसी घटना, सरकारी योजना, रोजगार अवसर अथवा कृषि संबंधी सूचना के लिए केवल स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों पर निर्भरता आवश्यक नहीं रह गई है। इस दृष्टि से डिजिटलीकरण ग्रामीण शक्तिसंबंधों में भी परिवर्तन की संभावना उत्पन्न करता है।-

8. ग्रामीण शिक्षा पर डिजिटलीकरण का प्रभाव

शिक्षा ग्रामीण डिजिटलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। स्मार्टफोन, ऑनलाइन कक्षाएँ, शैक्षिक वीडियो, डिजिटल पुस्तकें और ऑनलाइन परीक्षा सामग्री ने विद्यार्थियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए डिजिटल माध्यम ऐसी अध्ययन सामग्री तक पहुँच प्रदान कर सकता है जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षण ने भौगोलिक दूरी के महत्त्व को कुछ सीमा तक कम किया है। विद्यार्थी घर अथवा गाँव में रहकर विभिन्न विषयों के व्याख्यान, अभ्यास प्रश्न तथा परीक्षा संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों का विस्तार हुआ है।

हालाँकि इसका दूसरा पक्ष डिजिटल असमानता है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास व्यक्तिगत स्मार्टफोन, पर्याप्त डेटा, स्थिर नेटवर्क अथवा शांत अध्ययन वातावरण उपलब्ध नहीं होता। डिजिटल शिक्षा का वास्तविक लाभ डिजिटल कौशल पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार डिजिटलीकरण शिक्षा में अवसरों का विस्तार करता है, किंतु सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को स्वतः समाप्त नहीं करता।

9. रोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डिजिटल तकनीक ने ग्रामीण रोजगार की अवधारणा को भी प्रभावित किया है। पूर्व में रोजगार संबंधी जानकारी स्थानीय नेटवर्क, समाचारपत्र या रोजगार कार्यालयों पर अधिक निर्भर थी। वर्तमान में ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया तथा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सरकारी और निजी रोजगार संबंधी सूचनाएँ अपेक्षाकृत शीघ्र उपलब्ध हो सकती हैं।

डिजिटल भुगतान ने ग्रामीण आर्थिक व्यवहार में भी परिवर्तन किया है। छोटे व्यापारी, दुकानदार और सेवा प्रदाता डिजिटल लेन देन को अपनाकर नकद के अतिरिक्त भुगतान विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल-भुगतान प्रणालियों से वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

डिजिटल माध्यम स्वरोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण युवा ऑनलाइन सेवाएँ, ई कॉमर्स से संबंधित-गतिविधियाँ, डिजिटल दस्तावेज सेवाएँ तथा अन्य तकनीक आधारित कार्य अपना सकते हैं।-Common Service Centres का Village Level Entrepreneur मॉडल इस परिवर्तन का संस्थागत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

फिर भी डिजिटल रोजगार में आवश्यक कौशल, उपकरण और विश्वसनीय इंटरनेट की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। डिजिटल दक्षता से वंचित ग्रामीण व्यक्ति इन नए अवसरों का लाभ लेने में पीछे रह सकता है। इसलिए रोजगार के संदर्भ में डिजिटलीकरण अवसर और असमानता दोनों को साथ लेकर चलता है।

10. सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव

डिजिटलीकरण ने ग्रामीण सामाजिक संबंधों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरी के बावजूद लोगों को निरंतर संपर्क में रहने की सुविधा दी है। रोजगार अथवा शिक्षा के कारण बाहर रहने वाले परिवार के सदस्य वीडियो कॉल और संदेश के माध्यम से परिवार से जुड़े रह सकते हैं। इस प्रकार प्रवास के बावजूद पारिवारिक संपर्क बनाए रखने में डिजिटल माध्यमों की सकारात्मक भूमिका है।

दूसरी ओर प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के स्थान पर आभासी संपर्क की बढ़ती प्रवृत्ति ग्रामीण सामुदायिक जीवन के स्वरूप को प्रभावित कर सकती है। युवा पीढ़ी का अधिक समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर व्यतीत होना पारिवारिक संवाद तथा सामुदायिक सहभागिता में बदलाव ला सकता है। पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण के साथ एक नया डिजिटल सामाजिक क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसमें व्यक्ति स्थानीय समुदाय के अतिरिक्त दूरस्थ समूहों और विचारों से भी प्रभावित होता है। सोशल मीडिया ने ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं में भी परिवर्तन किया है। जीवनशैली-, उपभोग, रोजगार, शिक्षा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के नए प्रतिमान डिजिटल माध्यम से गाँव तक पहुँच रहे हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच सांस्कृतिक दूरी कुछ स्तरों पर कम होती दिखाई देती है।

11. महिलाओं और डिजिटलीकरण

ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में डिजिटलीकरण का प्रभाव विशेष महत्व रखता है। डिजिटल माध्यम महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं और रोजगार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। घर से बाहर जाने पर सामाजिक अथवा पारिवारिक प्रतिबंधों का सामना करने वाली महिलाओं के लिए डिजिटल माध्यम सूचना और सेवाओं तक पहुँच का वैकल्पिक साधन बन सकते हैं।

इसके बावजूद केवल परिवार में मोबाइल फोन उपलब्ध होना महिला के डिजिटल सशक्तिकरण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। फोन पर नियंत्रण किसका है, महिला स्वतंत्र रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सकती है या नहीं तथा उसमें आवश्यक डिजिटल कौशल है या नहीं—ये प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण भारतीय संदर्भ पर हुए अध्ययनों में स्मार्टफोन स्वामित्व और इंटरनेट उपयोग की स्वायत्तता में लैंगिक असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

इसलिए फतेहपुर के ग्रामीण समाज में महिलाओं पर डिजिटलीकरण के प्रभाव का अध्ययन करते समय पहुँच, स्वामित्व, कौशल और उपयोग की स्वतंत्रता को अलग अलग-आयामों के रूप में देखना आवश्यक है।

12. डिजिटल विभाजन और सामाजिक असमानता

डिजिटलीकरण का सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय प्रश्न डिजिटल विभाजन है। डिजिटल विभाजन केवल इंटरनेट उपलब्ध और अनुपलब्ध होने का अंतर नहीं है। यह उपकरण की गुणवत्ता, इंटरनेट की गति, डिजिटल साक्षरता, भाषा, आय, शिक्षा और तकनीक के प्रभावी उपयोग की क्षमता से भी संबंधित है।

भारत में सामाजिक आधारित डिजिटल विभाजन-आर्थिक असमानताएँ डिजिटल असमानता को प्रभावित करती हैं। जाति-पर किए गए एक अध्ययन में शिक्षा और आय संबंधी असमानताओं को डिजिटल पहुँच के अंतर के प्रमुख कारकों में पाया गया। इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं की इंटरनेट पहुँच में मौजूद अंतर यह संकेत देता है कि तकनीकी विस्तार के बावजूद सामाजिक संरचना डिजिटल अवसरों को प्रभावित करती रहती है।

अतः फतेहपुर में डिजिटलीकरण का मूल्यांकन करते समय यह देखना आवश्यक है कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, महिलाएँ, बुजुर्ग, कम शिक्षित व्यक्ति और सामाजिक रूप से वंचित समूह डिजिटल परिवर्तन में समान रूप से भागीदारी कर पा रहे हैं।

13. डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण सशक्तिकरण

डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल मोबाइल चलाना नहीं है। इसमें ऑनलाइन जानकारी खोजना, उसकी विश्वसनीयता समझना, डिजिटल भुगतान सुरक्षित रूप से करना, ऑनलाइन आवेदन भरना, साइबर धोखाधड़ी की पहचान करना और डिजिटल गोपनीयता को समझना भी सम्मिलित है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) इसी संदर्भ में उल्लेखनीय पहल रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार छह करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता को नीति स्तर पर सामाजिक समावेशन से जोड़ा गया है।

डिजिटल रूप से साक्षर ग्रामीण व्यक्ति सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, शिक्षा और रोजगार संबंधी सुविधाओं का अधिक स्वतंत्रता से उपयोग कर सकता है। इसके विपरीत डिजिटल ज्ञान का अभाव व्यक्ति को दूसरे लोगों अथवा सेवा केंद्रों पर निर्भर बनाए रख सकता है। इसलिए डिजिटल साक्षरता ग्रामीण सशक्तिकरण की केंद्रीय शर्त है।

14. डिजिटलीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ

ग्रामीण डिजिटलीकरण के सकारात्मक प्रभावों के साथ अनेक समस्याएँ भी सामने आती हैं। नेटवर्क की गुणवत्ता, स्मार्टफोन की लागत, डेटा व्यय, बिजली की उपलब्धता और तकनीकी ज्ञान की कमी इसके आधारभूत अवरोध हैं। इसके अतिरिक्त साइबर धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, OTP संबंधी ठगी, गलत सूचना तथा व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा जैसी नई समस्याएँ ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के सामने उपस्थित हुई हैं।

सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं के तीव्र प्रसार की संभावना भी बढ़ती है। डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण उपयोगकर्ता सही और गलत सूचना में अंतर करने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल पहुँच के विस्तार के साथ डिजिटल सुरक्षा और मीडिया साक्षरता को भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महत्व देना आवश्यक है।

15. समाजशास्त्रीय विश्लेषण

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से डिजिटलीकरण को सामाजिक परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो सामाजिक संस्थाओं, भूमिकाओं, संबंधों और अवसरों की संरचना को प्रभावित करती है। तकनीक स्वयं सामाजिक परिवर्तन का अकेला कारण नहीं है; उसका प्रभाव उस सामाजिक संरचना से निर्धारित होता है जिसमें उसका प्रयोग किया जाता है।

फतेहपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक ही डिजिटल तकनीक अलग अलग सामाजिक समूहों के लिए अलग परिणाम उत्पन्न कर सकती है। शिक्षित युवा के लिए स्मार्टफोन रोजगार और शिक्षा का साधन हो सकता है, छोटे व्यापारी के लिए डिजिटल भुगतान का माध्यम, किसान के लिए सूचना का स्रोत और विद्यार्थी के लिए अध्ययन सामग्री प्राप्त करने का साधन। वहीं डिजिटल कौशल से वंचित व्यक्ति के लिए यही तकनीक निर्भरता और असुरक्षा का कारण भी बन सकती है।

इस प्रकार ग्रामीण डिजिटलीकरण में दो समानांतर प्रक्रियाएँ दिखाई देती हैं—डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल असमानता। समाजशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्संबंध को समझना होना चाहिए।

16. प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन के सैद्धांतिक एवं द्वितीयक स्रोत आधारित विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटलीकरण ने ग्रामीण समाज में सूचना और सेवाओं तक पहुँच के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया है। शिक्षा में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता, रोजगार संबंधी सूचनाओं तक पहुँच, डिजिटल वित्तीय लेन देन तथा सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन विस्तार ने ग्रामीण-नागरिकों के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं।

इसके साथ सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आया है। डिजिटल संचार ने भौगोलिक दूरी को कम किया है, लेकिन प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क और पारंपरिक सामुदायिक संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन की संभावना भी बढ़ी है। ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाएँ अधिक व्यापक हुई हैं तथा वे स्थानीय सीमाओं से बाहर उपलब्ध शिक्षा, रोजगार और जीवन शैली के विकल्पों से परिचित हो रहे हैं।

इसके बावजूद डिजिटलीकरण का प्रभाव सभी ग्रामीण नागरिकों पर समान नहीं माना जा सकता। शिक्षा, आय, लिंग, आयु और डिजिटल कौशल में अंतर डिजिटल अवसरों की प्राप्ति को प्रभावित करता है। इसलिए केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि को पूर्ण डिजिटल समावेशन नहीं माना जा सकता।

17. सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की गुणवत्ता को और मजबूत किया जाना चाहिए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विश्वसनीय डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तथा कम शिक्षित नागरिकों के लिए विशेष डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के अतिरिक्त साइबर सुरक्षा, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और सूचना की सत्यता की पहचान करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल कौशल को स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी आवश्यक है।

CSC तथा अन्य डिजिटल सेवा केंद्रों को केवल ऑनलाइन आवेदन केंद्र के रूप में न देखकर ग्रामीण डिजिटल सहायता एवं प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है। महिलाओं की स्वतंत्र डिजिटल पहुँच बढ़ाने तथा साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित किया जाना चाहिए।

18. निष्कर्ष

डिजिटलीकरण भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। फतेहपुर जनपद के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता इसलिए अधिक है क्योंकि विस्तृत ग्रामीण संरचना में शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं तथा सामाजिक संपर्क से जुड़ी अनेक आवश्यकताओं को डिजिटल माध्यम नए स्वरूप में प्रभावित कर रहे हैं।

डिजिटल तकनीक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य सूचना संबंधी दूरी को कम करने, शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों को व्यापक बनाने तथा सरकारी एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाने की क्षमता रखती है। साथ ही डिजिटल विभाजन, लैंगिक असमानता, डिजिटल निरक्षरता, साइबर जोखिम और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएँ यह स्पष्ट करती हैं कि तकनीकी विस्तार अपने आप सामाजिक समानता सुनिश्चित नहीं करता।

अतः ग्रामीण डिजिटलीकरण की सफलता का वास्तविक मापदंड केवल इंटरनेट कनेक्शन अथवा स्मार्टफोन की संख्या नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि ग्रामीण नागरिक तकनीक का कितना स्वतंत्र, सुरक्षित, सार्थक और समानतापूर्ण उपयोग कर पा रहे हैं। फतेहपुर जैसे जनपदों में समावेशी डिजिटल विकास के लिए तकनीकी अवसंरचना के साथ डिजिटल शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और स्थानीय स्तर पर कौशल विकास को समान प्राथमिकता देना आवश्यक है।

संदर्भ सूची

- [1]. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. Digital India Programme. नई दिल्ली।
- [2]. भारत सरकार, संचार मंत्रालय. Digital and Broadband Connectivity. Press Information Bureau, 2025.
- [3]. भारत सरकार. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA). इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- [4]. Digital India. Our Pillars: Public Internet Access Programme. Ministry of Electronics & Information Technology.
- [5]. भारत सरकार. Common Services Centres Scheme. National Portal of India.
- [6]. Census of India. (2011). District Census Handbook: Fatehpur, Uttar Pradesh. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
- [7]. जिला प्रशासन फतेहपुर. Demography: District Fatehpur. उत्तर प्रदेश सरकार।
- [8]. Ministry of Communications, Government of India. (2024). Universal Connectivity and Digital India Initiatives Reaching to All Areas, Including Tier-2/3 Cities and Villages.
- [9]. Ministry of Communications, Government of India. (2025). Digital and Broadband Connectivity. Press Information Bureau.
- [10]. Ministry of Electronics & Information Technology. (2025). Digital India Expands: Digital Inclusion in SC/ST Areas Strengthened Through CSCs, PMGDISHA and BharatNet.
- [11]. Iqbal, R. (2021). Gendering of Smartphone Ownership and Autonomy among Youth: Narratives from Rural India.
- [12]. Vaidehi, R., Reddy, A. B., & Banerjee, S. (2021). Explaining Caste-based Digital Divide in India.
- [13]. Shruthi, K. A., Ihita, G. V., & Chaudhari, S. (2021). A Survey on Rural Internet Connectivity in India.
- [14]. National Family Health Survey (NFHS-5). (2019–21). India and Uttar Pradesh Fact Sheets. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
- [15]. Telecom Regulatory Authority of India. The Indian Telecom Services Performance Indicators. TRAI, New Delhi.